Dr.Raman Kumar thakur

Assistant professor (Guest) Department of Economics, D.B.College, Jaynagar, Madhubani.

Class:-B.A.part-1(H.)Date:-06-10-2020.Lecture n.-05.

Topic:- "अर्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की सीमाएं" (Limitations of Monetry policy in Under-Developed Countries)

:- अर्ध-विकसित देशों में विभिन्न कारणों से मौद्रिक नीति की सफल प्रयोग काफी सीमित रह जाता है भारत जैसे विकासशील देश में मौद्रिक नीति प्रभावशील नहीं हो पा रही है जिसके निम्नांकित कारण है:-1). संगठित मुद्रा बाजार की कमी:- प्रोफेसर ब्रह्मानंद के अनुसार प्राय: विकासशील देशों में मुद्रा बाजार काफी असंगठित रहता है जिसके कारण बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएं बैंक कोष में परिवर्तन इत्यादि का देश की साख व्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। इन देशों में बैंक दर में वृद्धि से भी साख का संकुचन नहीं हो पाता क्योंकि व्यवसायिक बैंक केंद्रीय बैंक पर आश्रित नहीं होते ब्याज दर बढ़ने से इन बैंकों के पास जमा राशि बढ़ जाती है। इस प्रकार वे साख निर्माण का कार्य पूर्ववत ही करते रहते हैं। इन देशों में प्रतिभूतियों का बाजार भी काफी और विकसित रहता है जिसके कारण खुले बाजार की क्रियाएं भी

सफल नहीं हो पाती। प्रोफ़ेसर मेयर के शब्दों में "संगठित मुद्रा बाजार की अपेक्षा असंगठित मुद्रा बाजार का बड़ा आकार और फिर इन दोनों बाजारों में प्रभावी संबंध का ना होना अर्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए बनाई गई मौद्रिक नीति की सफलता की संभावनाओं को छीन कर देता।"

2). अमौद्रिक क्षेत्र की विशालता:- इन देशों में अमौद्रीक क्षेत्र काफी विशाल और व्यापक होता है। इस क्षेत्र में मुद्रा के परिमाण अथवा ब्याज दर में परिवर्तनों का आर्थिक क्रियाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।

3). संगठित बिल बाजार की कमी:- प्रायःअर्ध विकसित देशों में संगठित बिल बाजार की कमी रहती है समय कटौती गृह, बट्टा गृह इत्यादि की कमी से साख प्रणाली ठीक से काम नहीं कर पाती मुद्रा बाजार के विभिन्न उप बाजारों का अभाव रहता है और उनके बीच संयोग बहुत ही कम होता है। 4). अव्यवस्थित व्याज- संरचना:- अर्ध विकसित देशों में ब्याज संरचना काफी अव्यवस्थित रहती है। सम्नवित ब्याज संरचना का अभाव रहता है ब्याज दरों में समरूपता नहीं पाई जाती है बैंक दर बाजार ब्याज दर तथा बट्टा दर में काफी अंतर रहता है ब्याज दर में स्थानगत भिन्नताएं भी होती है इस तरह अर्थव्यवस्था में प्रचलित विभिन्न ब्याज दरों तथा बैंक दर में

कोई निश्चित संबंध नहीं होता यही वजह है कि इन देशों में मौद्रिक नीति उतनी कारगर नहीं हो पाती।

5). बैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण अर्ध विकसित देशों में बैंकिंग संस्थाएं पूर्णतया केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में नहीं रहती है और ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति के नियंत्रण के तरीके संपूर्ण मुद्रा बाजार पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं ,कुछ बैंकिंग संस्थाएं नियंत्रण के बाहर होने से केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के बीच समन्वय का अभाव रहता है, फलत: मौद्रिक नीति का प्रभाव क्षेत्र घट जाता है।

6). स्वतंत्र कीमत प्रणाली की कमी मौद्रिक नीति की आवश्यक शर्त है कि कीमत प्रणाली स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करें किंतु विकासशील देशों में स्वतंत्र कीमत प्रणाली की कमी रहती है इन देशों में परियोजनाएं प्रायः देर से प्रतिफल देती है जिससे कीमतें बढ़ जाती है कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है जिसके कारण मुद्रा बाजार एवं वस्तु बाजार दोनों ही नियंत्रण से प्रभावित होते हैं तथा जमाखोरी, मुनाफाखोरी, तस्करी, कालाबाजारी एवं राशनिंग जैसी प्रवृत्तिया बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। भारत जैसे देश में नियंत्रित कीमत नहीं का विशेष महत्व है ।